मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) ने विश्व मत्स्य पालन दिवस (WFD) 2024 मनाया

WFD 2024 थीम: भारत का नीला परिवर्तन: लघु-स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को मजबूत करना।

शुरू की गई प्रमुख पहल

· डेटा-संचालित नीति निर्माण के लिए 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना।

· सतत शार्क प्रबंधन के लिए शार्क पर राष्ट्रीय कार्य योजना।

· श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के सहयोग से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में IUU (अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित) मत्स्य पालन को रोकने के लिए IUU (अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित) मत्स्य पालन पर क्षेत्रीय कार्य योजना के लिए भारत का समर्थन।

· समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन-खाद्य और कृषि संगठन (IMO-FAO) ग्लोलिटर साझेदारी परियोजना।

· ऊर्जा-कुशल, कम लागत वाले समुद्री मछली पकड़ने के ईंधन को बढ़ावा देने के लिए रेट्रोफिटेड LPG किट के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ।

· तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण द्वारा तटीय जलीय कृषि फार्मों के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करने के लिए नई एकल खिड़की प्रणाली।

· केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला, जबकि तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य के रूप में मान्यता दी गई।

मत्स्य पालन क्षेत्र का महत्व

· आजीविका प्रदान करता है: लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों को, जबकि मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करता है।

· पोषण मछली पशु प्रोटीन का एक किफायती और समृद्ध स्रोत होने के कारण, भूख और पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए सबसे स्वस्थ विकल्पों में से एक है।

· आर्थिक विकास: मछली उत्पादन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1% और कृषि सकल घरेलू उत्पाद (एफएओ, 2018) में 5% से अधिक का योगदान देता है।

भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में

· दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, वैश्विक उत्पादन में 8% का योगदान देता है, जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, झींगा उत्पादन और निर्यात में अग्रणी है।

· कैप्चर फिशरीज में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक।

मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहल

· प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई)

· प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएमकेएसवाई)

· राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 2006 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।

· मत्स्य अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)

रूस के राष्ट्रपति ने संशोधित परमाणु सिद्धांत (एनडी) को मंजूरी दी है

रूस ने अपने 2020 एनडी को अपडेट किया है, जिसमें दुश्मनों को रोकने और संभावित उपयोग परिदृश्यों को परिभाषित करने में परमाणु हथियारों की भूमिका की पुष्टि की गई है।

· परमाणु सिद्धांत: यह परमाणु हथियारों के उद्देश्य, विकास और तैनाती के साथ-साथ उनके इच्छित उपयोग को परिभाषित करता है।

रूस का संशोधित परमाणु सिद्धांत (एनडी)

· परमाणु हमले की विस्तारित परिभाषा: परमाणु राज्य द्वारा समर्थित किसी गैर-परमाणु राज्य द्वारा रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण को संयुक्त हमले के रूप में माना जाता है, जो परमाणु प्रतिशोध को उचित ठहराता है।

o यह स्पष्ट रूप से उन देशों को लक्षित करता है जो अपने क्षेत्रों का उपयोग रूस के विरुद्ध आक्रामकता के लिए करने की अनुमति देते हैं।

· परमाणु प्रतिक्रिया सीमा को कम करना: रूसी एनडी राज्य के अस्तित्व की रक्षा से बढ़कर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने तक विस्तारित हो गया।

o बेलारूस को औपचारिक रूप से रूस के परमाणु छत्र के नीचे रखा गया।

· संभावित परमाणु प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने वाले नए जोखिमों में शामिल हैं: रूसी सीमाओं के पास सैन्य गठबंधन और बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का विस्तार; रूसी सीमाओं के करीब दुश्मन के सैन्य बुनियादी ढांचे की स्थिति।

रूस के संशोधित एनडी का संभावित प्रभाव

· बढ़ी हुई परमाणु वृद्धि: संशोधित एनडी सामरिक परमाणु युद्ध का उपयोग करने की संभावना को बढ़ाता है।

· परमाणु अप्रसार व्यवस्था को कमजोर करना: संशोधित सिद्धांत राज्यों को परमाणु हथियार कार्यक्रमों को छोड़ने के लिए राजी करने में कठिनाई बढ़ा सकता है।

· अविश्वास में वृद्धि: रूस की कम परमाणु सीमा और "चरम परिस्थितियों" की विस्तारित परिभाषा रूस और अमेरिका के बीच अविश्वास को बढ़ा सकती है।

· अविश्वास में वृद्धि: रूस की कम परमाणु सीमा और "चरम परिस्थितियों" की विस्तारित परिभाषा रूस और अमेरिका के बीच अविश्वास को बढ़ा सकती है।

· भारत का परमाणु सिद्धांत (2003):

· पहले इस्तेमाल नहीं: भारत पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा।

· विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध: भारत संभावित हमलावरों को रोकने के लिए न्यूनतम परमाणु शस्त्रागार बनाए रखेगा।

· बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई: परमाणु हमले की स्थिति में, भारत बड़े पैमाने पर परमाणु हमले के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा।

· नागरिक नियंत्रण: परमाणु कमान प्राधिकरण (एनसीए) के माध्यम से नागरिक नेतृत्व के पास परमाणु हथियारों पर अंतिम अधिकार है।

· गैर-परमाणु राज्यों के खिलाफ गैर-उपयोग: भारत गैर-परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा।

जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट CoP-29 में जारी की गई

रिपोर्ट लोगों, स्थान और ग्रह पर जलवायु कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य पर जोर देती है (छवि देखें)।

स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

प्रत्यक्ष प्रभाव:

गैर-संचारी रोग (एनसीडी): जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण एनसीडी से होने वाली 85% मौतों का कारण बनते हैं।

गर्मी का तनाव: जलवायु परिवर्तन के कारण 2023 में लोगों को स्वास्थ्य के लिए ख़तरा पैदा करने वाली गर्मी के 50 दिन और झेलने पड़ेंगे। मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य: समय से पहले जन्म, कम वज़न, मातृ मृत्यु, प्रजनन क्षमता में कमी आदि। अप्रत्यक्ष प्रभाव: गरीबी और हाशिए पर जाने की दर में वृद्धि; खाद्य और जल सुरक्षा के लिए ख़तरा; संघर्ष

और पलायन में वृद्धि आदि। 2023 में, मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20.3 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। मुख्य अनुशंसाएँ मानव, पशु और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संबंधों को संबोधित करने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण लागू करें स्वास्थ्य।

शोषणकारी आर्थिक प्रणालियों से परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण।

जलवायु वित्त और हानि एवं क्षति निधि व्यवस्था पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य को राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में एकीकृत करें। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) आदि।

की गई पहल: जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर नेटवर्क (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक कार्यक्रम), आदि

भारत, मालदीव ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन के लिए समझौता किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

· भारत रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के अपने प्रयासों के तहत स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

मुद्रा (रुपये) के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में:

· मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण को राष्ट्रीय मुद्रा के बुनियादी कार्यों के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो लेखा इकाई, विनिमय माध्यम और मूल्य के भंडारण के रूप में कार्य करता है।

o उदाहरण के लिए, चालू खाता लेनदेन और विदेशी व्यापार के लिए रुपये को बढ़ावा देना शामिल है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व

· काउंटर ट्रेड जोखिम: रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण घरेलू फर्मों को स्थानीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चालान और निपटान करने में सक्षम बनाता है, जिससे विनिमय दर जोखिम कम हो जाता है।

· व्यापक वित्तीय पहुँच: घरेलू संस्थाएँ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का दोहन कर सकती हैं क्योंकि ।R पूंजी की लागत को कम करता है और वित्तपोषण विकल्पों का विस्तार करता है।

· रिजर्व प्रबंधन: बड़े विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता को कम करता है, संबंधित लागत और बाहरी कमजोरियों को कम करता है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियाँ

· प्रारंभिक चरणों में महत्वपूर्ण मुद्रा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है

· वैश्विक मुद्रा आपूर्ति दायित्व घरेलू मौद्रिक नियंत्रण आवश्यकताओं (ट्रिफ़िन दुविधा) के साथ संघर्ष करेंगे

· अप्रतिबंधित सीमा पार पूंजी प्रवाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय झटकों के प्रति जोखिम में वृद्धि।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में उठाए गए कदम

· RBI ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति दी है।

· रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बढ़ावा देने के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता प्रणाली।

· भारत ने जापान, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन (CCAC) और FAO ने वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की

अज़रबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र COP29 में लॉन्च की गई, यह एक दशक से अधिक समय में पूरी तरह से N2O पर केंद्रित पहली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है।

रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष

· यदि N2O उत्सर्जन अपनी वर्तमान दर (वर्तमान हिस्सा 0.1° C) पर बढ़ता रहा, तो वैश्विक तापमान को 1.5° सेल्सियस तक सीमित करने का कोई प्रशंसनीय मार्ग नहीं है।

· 1980 के बाद से N2O के मानवजनित उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर 40% की वृद्धि हुई है, जिसमें से लगभग 75% सिंथेटिक उर्वरकों और खाद के कृषि उपयोग से उत्पन्न हुआ है।

· N2O ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख पदार्थ है, जो हानिकारक UV एक्सपोजर को बढ़ाता है और मोतियाबिंद (0.2-0.8%) और त्वचा कैंसर (2-10%) के जोखिम को बढ़ाता है।

N2O उत्सर्जन को कम करने के लिए सुझाए गए उपाय

कृषि: बढ़ी हुई दक्षता वाले उर्वरकों, नाइट्रिफिकेशन अवरोधकों, धीमी गति से निकलने वाले फॉर्मूलेशन आदि का उपयोग करके N2O उत्सर्जन को कम करना।

उद्योग: थर्मल विनाश या उत्प्रेरक प्रक्रियाओं से एडिपिक एसिड (सिंथेटिक फाइबर, फोम में उपयोग किया जाता है) और नाइट्रिक एसिड (उर्वरक उत्पादन में उपयोग किया जाता है) से उत्सर्जन के उपचार में 90-99% दक्षता प्राप्त की जा सकती है।

जीवाश्म ईंधन में कमी: परिवहन, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर स्विच करना।

खाद प्रबंधन: पशु आहार में पोषक तत्वों के इनपुट को संतुलित करके, चराई की तीव्रता को कम करके, खाद का अवायवीय पाचन आदि।

बहुपक्षीय विकल्प: जैसे गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल लंबी दूरी के ट्रांसबाउंड्री वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन के तहत अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर लक्ष्य रखता है।

N_2O के बारे में

· यह एक लंबे समय तक रहने वाली ग्रीनहाउस गैस है जो CO2 से लगभग 270 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है।

· इसका वायुमंडलीय जीवनकाल लगभग 114 वर्ष है।

· स्रोत: प्राकृतिक (मिट्टी और महासागरों में सूक्ष्मजीवी गतिविधि) और मानवजनित (उर्वरक, अपशिष्ट जल आदि)।

· अन्य मुख्य तथ्य: अकार्बनिक गैस जिसे आमतौर पर 'हँसी गैस' के रूप में जाना जाता है; स्पष्ट, रंगहीन और गंधहीन गैस; पानी में घुलनशील और इसके वाष्प हवा से भारी होते हैं।

CCAC के बारे में

· 2012 में स्थापित और UNEP के भीतर बुलाई गई, CCAC 160 से अधिक सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की एक स्वैच्छिक साझेदारी है। भारत 2019 में CCAC में शामिल हुआ।

· यह शक्तिशाली लेकिन अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करने के लिए काम करता है जो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण दोनों को बढ़ावा देते हैं।

एंटीगुआ और बारबुडा (राजधानी: सेंट जॉन्स)

प्रधानमंत्री ने जॉर्जटाउन, गुयाना में दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

राजनीतिक विशेषताएं

एंटीगुआ और बारबुडा एक कैरिबियन द्वीप है जो पूर्वी कैरिबियन सागर में लेसर एंटिलीज़ में स्थित है।

समुद्री सीमा: एंगुइला (यूनाइटेड किंगडम) और सेंट बार्थेलम उत्तर-पश्चिम में y (फ्रांस), पश्चिम में सेंट किट्स और नेविस संघ, दक्षिण-पश्चिम में मोंटसेराट (यूनाइटेड किंगडम) और दक्षिण-पूर्व में ग्वाडेलोप (फ्रांस) है।

भौगोलिक विशेषताएँ

एंटीगुआ की तटरेखा जटिल है, जिसमें खाड़ियाँ और हेडलैंड हैं जो चट्टानों और उथले पानी से घिरे हैं।

सबसे ऊँची चोटी: माउंट ओबामा।

कैरेबियन द्वीपों के बारे में (जिन्हें वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है)

अटलांटिक महासागर में, फ्लोरिडा के दक्षिण-पूर्व, मध्य अमेरिका के पूर्व और दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है।

कैरेबियन में उत्तर-पश्चिम में ग्रेटर एंटिलीज़ के द्वीप और साथ ही दक्षिण-पूर्व में लेसर एंटिलीज़ द्वीप शामिल हैं।